भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 613

28 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

अपशिष्ट, सेपटेज और मल-जल प्रबंधन

613. श्री सुधाकर सिंहः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार के शहरी क्षेत्रों, विशेषकर बक्सर में अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण, मल-जल और सेपटेज प्रबंधन में सुधार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की बिहार, विशेषकर बक्सर को मल-जल और सेपटेज प्रबंधन हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): भारत सरकार ने बिहार सहित देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता उपलब्ध करवाने और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (एसबीएम-यू) का शुभारंभ किया था।

फेज़-1 में जमीनी स्तर पर किए गए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, सभी शहरों में सुरक्षित स्वच्छता और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के लक्ष्य को प्राप्त करने के विज़न के साथ 1 अक्टूबर, 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 का शुभारंभ किया गया।

बिहार में बक्सर सहित देश में शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, गैर-मोटरीकृत शहरी परिवहन और हरित स्थान व पार्क के मूलभूत

इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 जून, 2015 को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का शुभारंभ किया गया था।

शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने के लिए 1 अक्टूबर, 2021 को अमृत 2.0 का शुभारंभ किया गया है। अमृत 2.0 का लक्ष्य देश के 500 शहरों से लेकर सभी सांविधिक कस्बों तक जलापूर्ति में सार्वभौमिक कवरेज को बढ़ाकर जीवन को आसान बनाना है।

(ग) और (घ): 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार के बक्सर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। इसलिए, सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजना को अमृत और अमृत 2.0 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अमृत 2.0 के अंतर्गत, अब तक बिहार में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 5,195.36 करोड़ रुपये की लागत वाली 17 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 297.8 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान (एसटीपी) क्षमता का सृजन/संवर्धन शामिल है। बक्सर जिले के लिए, अमृत 2.0 के अंतर्गत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अब तक 261.47 करोड़ रुपये की लागत वाली एक सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 16.77 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान (एसटीपी) क्षमता का सृजन/संवर्धन शामिल है।

*****